



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 581]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 8, 2005/ज्येष्ठ 18, 1927

No. 581]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 8, 2005/JYAISTHA 18, 1927

विद्युत मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 8 जून, 2005

का. आ. 792(अ).—विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) (जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) 10 जून, 2003 से प्रवृत्त हुआ है;

और अधिनियम की धारा 86 की उपधारा(1) का खंड (ख) यह उपबंध करता है कि राज्य आयोग को वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा की जाने वाली विद्युत क्रय तथा इसकी उपापन प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी जिसके अंतर्गत वह कीमत भी है जिस पर विद्युत, राज्य में वितरण और प्रदाय के लिए विद्युत क्रय के करारों के माध्यम से उत्पादन कंपनियों या अनुज्ञप्तिधारियों से या अन्य स्रोतों से उपाप्त की जाएगी;

और समुचित आयोग को अधिनियम की धारा 62 की उपधारा(1) के खंड (क) के अनुसार उत्पादन कंपनी द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत का प्रदाय करने के लिए टैरिफ का अवधारण करने की शक्ति होगी;

और कुछ राज्य सरकारें हाइड्रो ऊर्जा स्थल के विकास से संबंधित शर्तों के अनुसरण में, विभिन्न हाइड्रो ऊर्जा उत्पादन कंपनियों द्वारा उत्पादित ऊर्जा से विद्युत निःशुल्क प्राप्त कर रही हैं;

और ऐसी राज्य सरकार को अधिनियम की धारा 62 की उपधारा (1) के खंड (क) के प्रयोजन के लिए अधिनियम की धारा 2 की उपधारा(28) के अनुसार "उत्पादन कंपनी" की परिभाषा में सम्मिलित नहीं किया गया है;

और हाइड्रो ऊर्जा उत्पादन कंपनियों से राज्य सरकार द्वारा प्राप्त निःशुल्क विद्युत के निपटान तथा संबंधित मामलों की दशा में, कठिनाइयां उद्भूत हुई हैं;

अब, अतः, केंद्रीय सरकार, अधिनियम की धारा 183 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऐसी विद्युत के निपटान के लिए राज्य सरकार के विवेकाधिकार की बाबत जो अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थातः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विद्युत(कठिनाईयों को दूर करना) (तीसरा) आदेश, 2005 है।
- (2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

2. राज्य सरकार द्वारा हाइड्रो ऊर्जा उत्पादन केंद्रों से प्राप्त निःशुल्क विद्युत का निपटान;

हाइड्रो उत्पादन केंद्रों से निःशुल्क विद्युत प्राप्त करने वाली राज्य सरकार को ऐसी विद्युत को ऐसी रीति से निपटान करने का विवेकाधिकार होगा जो वह अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उचित समझे:

परंतु यदि ऐसी विद्युत, राज्य सरकार द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी को बेची जाती है तो संबंधित राज्य आयोग को ऐसी कीमत को विनियमित करने की शक्ति होगी जिस पर ऐसी विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपाप्त की जाती है।

[फा. सं. 25/25/2004-आर एंड आर]

अजय शंकर, अपर सचिव

MINISTRY OF POWER

ORDER

New Delhi, the 8th June, 2005

S.O. 792(E).—Whereas the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) (hereinafter referred to as the Act), came into force on the 10th June, 2003;

And whereas the clause (b) of the sub-section (1) of section 86 of the Act provides that the State Commission shall have powers to regulate electricity purchase and procurement process of distribution licensees including the price at which electricity shall be procured from the generating companies or licensees or from other sources through agreements for purchase of power for distribution and supply within the State;

And whereas the Appropriate Commission has the power to determine the tariff for supply of electricity by a generating company to a distribution licensee in terms of clause (a) of sub-section (1) of section 62 of the Act;

And whereas some of the State Governments are getting free electricity from the power generated by various hydro power generating companies in pursuance of the conditions relating to the development of the hydro power site;

And whereas such a State Government is not covered in the definition of the “generating company” in terms of sub-section (28) of section 2 of the Act, for the purpose of clause (a) of sub-section (1) of section 62 of the Act;

And whereas difficulties have arisen in respect of disposal of free electricity received by the State Government from hydro power generating companies and related matters;

Now, therefore, the Central Government in exercise of its powers conferred by section 183 of the Act hereby makes this order in respect of discretion of the State Government to dispose off such electricity, not inconsistent with the provisions of the Act, namely:-

1. Short title and commencement:-

- (1) This order may be called the Electricity [Removal of Difficulty] (Third) Order, 2005.
- (2) It shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

2. Disposal of free electricity received by a State Government from hydro power generating stations:-

The State Government receiving free electricity from hydro power generating stations shall have discretion to dispose off such electricity in the manner it deems fit according to the provisions of the Act:

Provided that if such electricity is sold by the State Government to a distribution licensee, the concerned State Commission shall have powers to regulate the price at which such electricity is procured by the distribution licensee.

[F. No. 25/25/2004-R & R]

AJAY SHANKAR, Addl. Secy.